श्रीकांत रॉय और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 10874/2016)

16 नवंबर, 2016

[टी. एस. ठाकुर, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

न्यायिक सेवा-उच्च न्यायिक सेवा-चयन प्रक्रिया-अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों के लिए चयन-झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवाओं की शर्तें) नियम, 2001- संदर्भित 5 और 8-संशोधित नियमों के अनुसार रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदों का विभाजन-जिसके संदर्भ में, योग्यता-सह-श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पद-शेष 50 प्रतिशत पदों को समान रूप से विभाजित किया जाएगा, यानी सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से चयन द्वारा से 25 प्रतिशत और बार से सीधी भर्ती द्वारा से 25 प्रतिशत-सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति द्वारा से एडीजे के पदों को भरने के लिए अगस्त 2008 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया-उच्च न्यायालय को चुनौती-उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि 50 प्रतिशत पद पहले ही योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों द्वारा भरे जा चुके हैं, इसलिए बचे हुए 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों को सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से भरा जाना चाहिए। राज्य सरकार के सुसंगत रुख और उच्च न्यायपालिका (प्रशासनिक पक्ष) द्वारा दायर शपथ पत्र के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि 2008 में जारी पदोन्नति द्वारा एडीजे के पदों को भरने के लिए अधिसूचना इस आधार पर थी कि प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के पदों के खिलाफ कोई रिक्ति

उपलब्ध नहीं थी-उच्च न्यायपालिका ने प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के संबंध में रिक्त पदों के रूप में इन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं करने में स्पष्ट त्रुटि की-उच्च न्यायपालिका द्वारा "पद" और "रिक्ति" के बीच अंतर की अनदेखी की गई-एक बार जब यह पाया गया कि प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे के खिलाफ कोई रिक्ति प्रासंगिक समय पर उपलब्ध नहीं थी, तो निजी प्रतिवादी जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा से चयन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य थे।

न्यायालय ने प्रमुख सिविल अपील को अनुमति देते हुये और तीन संबंधित रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 जब पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अनुपात बनाए रखने का प्रावधान करने वाले संशोधित नियम 20 अगस्त 2004 को प्रभावी हो गए और संभावित अनुप्रयोग हो गए, तो 20 अगस्त 2004 को प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति प्रासंगिक हो जाएगी। [पैरा 12] [70-जी-एच]

1.2 नियम 8 के साथ पठित नियम 4 और 5 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि यह 2004 से पहले की गई 20.08.2004 नियुक्तियों के संशोधन से पहले मौजूद था, संबंधित समय पर लागू नियमों द्वारा शासित थे। उस व्यवस्था के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्ती कोटा कुल पदों का 33 प्रतिशत था, जो स्पष्ट रूप से संशोधित नियमों में अब निर्दिष्ट 25 प्रतिशत से अधिक था (जैसा कि 20.08.2004 पर संशोधित किया गया है)। विशेष रूप से, झारखंड राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष सी ए सं॰ 1867/2006 में एक शपथ पत्र दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उस समय झारखंड राज्य में सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत कोटे के खिलाफ कोई रिक्ति मौजूद नहीं थी। संशोधित नियमों को अधिसूचित किए जाने और 20 अगस्त 2004 से लागू होने के बाद यह शपथ पत्र 26 अगस्त 2008 को दायर किया गया था। इस प्रकार, झारखंड अधीनस्थ

न्यायाधीशों के सदस्यों में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 34 पदों को भरने के लिए अधिसूचना 2008 में इस आधार पर जारी की गई थी कि प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के पदों के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा दायर शपथ पत्र में अब भी इस रुख को दोहराया गया है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के खिलाफ एक निष्कर्ष दर्ज करने से पहले प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए रिक्त पदों के बारे में इन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं करने में स्पष्ट त्रुटि की और उनके इस रुख को अस्वीकार कर दिया कि प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। [पैरास 13,14] [71-ए; 72-सी-एफ]

1.3 एक बार जब यह पाया जाता है कि 30 अप्रैल, 2008 तक सीधी भर्ती के कोटे के खिलाफ कोई पद उपलब्ध नहीं था, तो झारखंड उच्च न्यायिक द्वारावा के संवर्ग में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने विवादित फैसले में रिक्तियों को भरने के प्रभाव को 25:25 के अनुपात में कम कर दिया जो अनिवार्य रूप से 30.04.2008 पर प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पदों के कोटे से अधिक होगा। यह रोस्टर बिंदु को बाधित करेगा और संशोधित नियम 8 के संदर्भ में अस्वीकार्य था। [पैरा 16] (76-ए-बी)

1.4 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 30 अगस्त 2008 तक प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे में कोई रिक्ति मौजूद नहीं थी, रिट याचिकाकर्ताओं (प्रमुख अपील में 4 से 11 उत्तरदाता), जो सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति द्वारा से नहीं, केवल प्रत्यक्ष भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते थे, के पास 2008 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। [पैरा 18] [78-ए-बी]

2. उच्च न्यायालय ने "पद" और "रिक्ति" के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर दिया। यदि प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा आवश्यक पद पहले ही समाप्त हो चुके थे, केवल इसलिए कि कुछ रिक्तियां होती हैं, तो इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति द्वारा सेवा में न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ यह खुला नहीं होगा। [पैरा 19] [78-बी-सी]

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य अन्यभारत संघ अन्य (2002) 4 एससीसी 247:2002 (2) एससीआर 712; राखी रे और अन्य. बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय अन्य (2010) 2 एससीसी 637:2010 (2) एस. सी. आर. 239-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2002 (2) एस. सी. आर. 712 पैरा 15 में निर्दिष्ट

2010 (2) एस. सी. आर. 239 पैरा 21 में निर्दिष्ट

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल याचिका संख्या 10874/2016

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के डब्ल्यू. पी. एस. सं. 4159/2008 में दिनांक 29.08.2008 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) 2013 की संख्या 300

डब्ल्यू. पी. (ग) 2014 की सं. 27 और 325

निधेश गुप्ता, अमरेंद्र शरण, अजीत कुमार सिन्हा, महाबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, रौणक सिंह, अमित कुमार, शौर्य, पुनीत वार्ष्णेय, राजीव शर्मा, सुमित कुमार, डॉ. कैलाश चंद, अंभोज कुमार सिन्हा, कृष्णानंद पांडे, हिमांशु शेखर, जामनेश

कुमार, देवाशीष भरुका, सुश्री मधुष्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, सुश्री मधुर ददलानी, जायेश गौरव, अनिल के झा, तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद वकास, आदित्य प्रताप सिंह, शिव राम शर्मा, सुश्री आशा गोपालन नायर, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए. एम. खानविलकर, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति अनुदत्त गई।

2. यह सामान्य निर्णय सभी चार याचिकाओं का निपटारा करेगा।

3. विशेष अवकाश याचिका (सिविल) सं. 9883/2009 से उत्पन्न होने वाली प्रमुख सिविल अपील, डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 4159/2008 दिनांक 29 अगस्त 2008 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले के खिलाफ निर्देशित है। उक्त रिट याचिका द्वारा, रिट याचिकाकर्ताओं (इसमें 4 से 11 प्रतिवादी) ने 31 अगस्त 2008 को निर्धारित सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 34 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी; और 23 अगस्त 2008 को निर्धारित योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत अधिकारियों से अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 18 पदों को भी भरने के लिए चुनौती दी थी। रिट याचिकाकर्ताओं (इसमें 4 से 11 प्रतिवादी) को विशुद्ध रूप से अस्थायी और पूर्व-संवर्ग के पदों के खिलाफ तदर्थ आधार पर वर्ष 2002 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर फास्ट ट्रैक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विवादित चयन प्रक्रिया अनुचित थी और 50 के अनुपात की आवश्यकता वाले संशोधित नियमों के जनादेश के अनुरूप नहीं थीः 25:25 योग्यता-सह-वरिष्ठता और उत्तीर्णता के आधार पर उप-न्यायाधीशों के बीच से पदोन्नति द्वारा 5 वर्ष से कम की सेवा वाले उप-न्यायाधीशों की सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा द्वारा से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति (चयन द्वारा से) और क्रमशः उच्च

न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर बार से सीधी भर्ती द्वारा। उक्त रिट याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यदि विवादित चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो यह संबंधित भर्ती नियमों का भंग होगा और संशोधित नियमों के नियम 8 के अनुसार रोस्टर का पालन करने के जनादेश का भी भंग होगा। उक्त रिट याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि उच्च न्यायालय 20 अगस्त 2004 से लागू हुए संशोधित नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर रिक्तियों को भरने के लिए पदों के अनुपात को गलती से जोड़ रहा था। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती, जैसा कि विवादित निर्णय के प्रारंभिक पैरा में उल्लेख किया गया है, 31 प्रतिशत अगस्त 2008 को होने वाली (अधीनस्थ न्यायाधीश/सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)) के बीच से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिए निर्धारित कोटा तक सीमित थी। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 4 में कहा है कि चुनौती केवल अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 42 पदों की सीमा तक है जिन्हें 25:25 के अनुपात में रोस्टर प्रणाली का पालन करके भरा जाना था उन पदों को सीमित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके अधीनस्थ न्यायाधीशों के पद से पदोन्नत लोगों के बीच समान रूप से विभाजित करने की आवश्यकता थी और बार से 25:25 के अनुपात में सीधी भर्ती की जानी थी विवादित फैसले के पैराग्राफ 10 के बाद, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाकर्ताओं की याचिका को बरकरार रखा और उच्च न्यायालय को निर्देश के अनुसार रिक्तियों को भरने का निर्देश जारी किया। विवादित निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार पढ़ता हैः

> “10. झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, जिसे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था, के अनुसरण में पालन की जाने वाली रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदों के विभाजन के संबंध में स्पष्टीकरण के आलोक में पार्टियों के वकील

को कुछ समय तक सुनने के बाद, हमारा विचार है कि 50 प्रतिशत पद पहले ही योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों द्वारा भरे जा चुके हैं, जिसके कारण 41 पद भरे गए थे, 42 से अधिक पदों को 25 प्रतिशत और 25 प्रतिशत में विभाजित किया जाना है, जिसका अर्थ है कि 21 पदों को सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीशों/सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) से पदोन्नति द्वारा भरा जाना है और 21 से अधिक पद बचे हैं जो 23 हैं। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि प्रतिवादी ने न केवल सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा भरे जाने वाले सभी 42 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, बल्कि वर्ष 2009 में उपलब्ध होने वाले पदों को भी विज्ञापन में शामिल किया गया है, जो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नहीं है और झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2001 के विपरीत भी है।

11. इसलिए, इस अदालत के पास परीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जो 31.08.2008 पर आयोजित होने वाली है और प्रतिवादी को बचे हुए पदों को आधे और आधे के अनुपात में विभाजित करने का निर्देश देता है, यानी 25 प्रतिशत और 25 प्रतिशत समान रूप से और उसके बाद सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा 21 पदों को भरने के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया और शेष 21 पदों को सीधे भर्तियों द्वारा भरना होगा, जिसके लिए भविष्य में प्रतिवादी द्वारा अभ्यास करना होगा।

12. चूंकि इस रिट याचिका में कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है और जो विवाद उठाया गया है, वह पहले उल्लिखित रोस्टर सिद्धांत के विपरीत पदों के विभाजन

के लिए दर्ज है, और वही सही पाया गया है, इसलिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए इंटरनेट पर जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।

नतीजतन, 31.8.2008 पर आयोजित होने वाली परीक्षा की प्रक्रिया को भी अलग रखा जाता है। तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति है, लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

4, अपीलार्थी, जो प्रासंगिक समय पर अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में काम कर रहे थे और अन्यथा पदोन्नति के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के पात्र थे, ने उपरोक्त निर्णय पर सवाल उठाने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

5. संज्ञानात्मक रिट याचिकाओं में अतिव्यापी मुद्दे शामिल हैं। हालाँकि, इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने 2010 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया, जो बार से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद के लिए एक विज्ञापन संख्या, 1/2010 के आधार पर शुरू हुई थी। ये याचिकाकर्ता नियुक्त होने में सफल नहीं हुए, क्योंकि योग्यता सूची में पहले 8 उम्मीदवारों ने प्रासंगिक अवधि के लिए अधिसूचित 8 रिक्तियों को समाप्त कर दिया। हालाँकि, उक्त रिट याचिकाकर्ताओं को योग्यता सूची में क्रम संख्या 9 पर रखा गया था। इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बार से सीधी भर्ती के लिए कुछ और पद उपलब्ध थे। यह विवाद, अनिवार्य रूप से, विशेष अवकाश याचिका (सिविल) सं. 9883/2009 से उत्पन्न सिविल अपील के परिणाम पर निर्भर है, जिसमें 2008 की चयन प्रक्रिया विषय वस्तु है। इन रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उच्च न्यायालय 2010 के लिए रिक्तियों की सही संख्या को अधिसूचित करने में विफल रहा था। 2010 में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की सही संख्या 13 होनी चाहिए। वास्तव

में, रिट याचिकाकर्ताओं ने रिक्तियों की इस संख्या पर पहुंचने के लिए अपनी धारणा बनाई है, जैसा कि रिट याचिका में किए गए अभिकथनों से पता चलता है।

6. उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने जवाबी हलफनामे दायर किए हैं। उच्च न्यायालय (प्रशासन पक्ष) का रुख था कि बार से सीधी भर्ती के लिए कोई रिक्ति 20.04.2008 पर मौजूद नहीं थी। यह कहा गया है कि वर्ष 2008 में, 30 अप्रैल, 2008 को वास्तविक रिक्ति और 31 मार्च 2009 तक प्रत्याशित रिक्ति को उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना इस प्रकार हैः

30.04.2008 पर वास्तविक रिक्ति	31.03.2009 तक अपेक्षित रिक्ति
उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा योग्यता-सह-श्रेष्ठता के आधार पर- 18	योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति- 11
सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदोन्नति (चयन द्वारा से)- 34	

ध्यान दें: राज्य सरकार द्वारा झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियमित आधार पर फास्ट ट्रैक न्यायालयों के 10 एडहॉक एडीजे को शामिल करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने की स्थिति में, न्यायालय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अक्षर सं. 6949/Apptt दिनांक 3 नवंबर 2007 और 2819/एप्ट दिनांक 11.04.2008, प्रोमोटरी कोटा में 30.04.2009 पर वास्तविक रिक्तियों को घटाकर 08 कर दिया जाएगा।"

2008 के लिए विवादित चयन प्रक्रिया की शुरुआत के बाद, उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय को निर्देश जारी किए गए

थे कि 42 रिक्तियों में से 21 रिक्तियों को सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीशों की पदोन्नति द्वारा और शेष 21 रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए। इसलिए यह मामला चयन समिति के पास भेजा गया था। इस बीच, हालांकि, न्यायिक अधिकारियों ने वर्तमान एस. एल. पी. के माध्यम से उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी (सिविल) सं. 9883/2009 जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रवर्तन पर अंतरिम रोक 9 अप्रैल, 2009 को दी गई थी। उक्त अंतरिम आदेश को बाद में 24 सितंबर 2010 को निम्नलिखित शर्तों में संशोधित किया गया थाः

> "2001 के टी सी 22 के बैच के साथ सूची बनाएँ। चूंकि मामला 2008 के विज्ञापन के चरण में लंबित है, इसलिए हम 2008 के विज्ञापन के अनुसार, इस विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान तक प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश देकर पिछली पीठ द्वारा पारित आदेश को संशोधित करते हैं। हालांकि, प्रक्रिया पूरी होने पर अगले आदेश तक रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा।"

अंतरिम आदेश के संशोधन के अनुसार, उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के माध्यम से 2008 की अधिसूचित रिक्तियों को भरने की चयन प्रक्रिया पूरी की। दायर एक और आवेदन पर, इस न्यायालय ने 5 अगस्त 2011 को उच्च न्यायालय को 2008 की उक्त चयन प्रक्रिया से संबंधित नियुक्तियां करने की अनुमति दी। उक्त आदेश इस प्रकार हैः

> "24 सितंबर 2010 के हमारे आदेश के संशोधन में, उच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के अधीन नियुक्तियां करने के लिए स्वतंत्र है। तदनुसार, अंतर्वर्ती आवेदन की अनुमति है।"

इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने नियम 4 (बी) और 4 (सी) के संदर्भ में रिक्तियों को भरने के लिए 2008 में जारी विज्ञापन के अनुसार उप-न्यायाधीश संवर्ग के 31 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उच्च न्यायालय ने 17 और अधिकारियों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को एक और सिफारिश प्रस्तुत की।

7. इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा यह दावा किया जाता है कि जब 2008 की चयन प्रक्रिया शुरू और पूरी हुई थी, तो प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के लिए कोई रिक्ति नहीं थी। शपथ पत्र में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्यक्ष कोटे की 8 रिक्तियों को संबंधित अवधि के लिए 4 नवंबर 2010 के उच्च न्यायालय के ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2010 में अधिसूचित किया गया था, जो इस प्रकार हैः

> "झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में वास्तविक रिक्तियां 18.07.2008 से लेकर आज तक मेमो 7671/एप्ट तक की अवधि के दौरान उपार्जित हुई हैं। रांची दिनांक 4 नवंबर, 2010 की प्रति वैज्ञानिक (डी), एन. आई. सी., झारखंड उच्च न्यायालय रांची को अग्रेषित की गई। उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त रिक्तियों को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की आधिकारिक वेबसाइट पर रखें।"

योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा	सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति (चयन द्वारा से)	बार से सीधी भर्ती द्वारा	कुलःरिक्तियां
28	08 या 09	07 या 08	44

उच्च न्यायालय ने उन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन सं. 01/2010 के

माध्यम से प्रक्रिया शुरू की। उक्त विज्ञापन के अनुसार, संबंधित रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ता अन्य उम्मीदवारों के साथ 29 सितंबर 2011 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा और 27 नवंबर 2011 को आयोजित मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए। केवल 32 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, जिन्हें 3 फरवरी 2012 को आयोजित वाइवा-वॉस के लिए बुलाया गया था। उन उम्मीदवारों में से, संबंधित रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं सहित केवल 15 उम्मीदवारों ने तीनों चरणों में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की। हालांकि, सफल उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार, उक्त रिट याचिकाकर्ताओं के नाम निचले स्थान पर रखे गए थे। इस प्रकार, सीधी भर्ती की प्रक्रिया द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों के खिलाफ नियुक्ति के लिए पहले 8 मेधावी उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2008 के लिए चयन प्रक्रिया के खिलाफ की गई उम्मीदवारों की नियुक्ति, उम्मीदवारों को इस बात से अवगत कराया गया था कि उनकी नियुक्ति विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 9883/2009 में इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन थी।

8. उच्च न्यायालय द्वारा यह दावा किया गया है कि संबंधित रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ता, जिन्होंने बाद की चयन प्रक्रिया में भाग लिया, उन्हें 2008 की चयन प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। उन्होंने 2010 के विज्ञापन संख्या 1 के आधार पर शुरू की गई चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसी तरह, वे 22 मार्च, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से वर्ष 2012 में अधिसूचित नई रिक्ति के संबंध में किसी भी राहत का दावा नहीं कर सकते हैं। वह अधिसूचना इस प्रकार हैः

संख्या 102/ए, झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा की रिक्तियों सहित भविष्य की रिक्तियों को 31.12.2012 तक निम्नलिखित तरीके से अधिसूचित किया जाता हैः-

"झारखंड उच्च न्यायालय, रांची अधिसूचना

नियम, 2001 के नियम 4 (बी) के तहत योग्यता-सह-वरिष्ठता (65 प्रतिशत) के आधार पर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति द्वारा	नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10 प्रतिशत) द्वारा से पदोन्नति (चयन द्वारा से)	बार से सीधी भर्ती (25 प्रतिशत)-नियम, 2001 के नियम 4 (ए) के तहत
57+7=64	निल	5 (+8*)

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त 69 ए अधिसूचित रिक्तियों पर नियुक्ति भी अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सिविल) संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

इसके अलावा, पहले की सभी विज्ञापित रिक्तियों को उपरोक्त तरीके से वापस लिया जाता है और उनका पुनर्गठन किया जाता है

ध्यान दें: प्रत्यक्ष भर्ती कोटे की 08 रिक्तियों को भरने की सिफारिश राज्य सरकार को पत्र संख्या 1959/एप्ट दिनांकित 10.02.2012 के माध्यम से आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए पहले ही की जा चुकी है और इस प्रकार इस कोटा के तहत 31.12.2012 तक रिक्ति O5 (पाँच) बनी हुई है।

तारीखः 22 मार्च, 2012

आदेश से,

महापंजीयक "

31 प्रतिशत दिसंबर 2012 को रिक्ति की स्थिति को संशोधित किया गया था

और 19 सितंबर 2012 की अधिसूचना के माध्यम से विधिवत अधिसूचित किया गया था, जो इस प्रकार हैः

"झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अधिसूचना

22 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 102/ए द्वारा अधिसूचित झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा की रिक्तियों की स्थिति को निम्नलिखित तरीके से संशोधित और अधिसूचित किया गया हैः-

नियम, 2001 के नियम 4 (बी) के तहत योग्यता-सह-वरिष्ठता (65 प्रतिशत) के आधार पर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति द्वारा	नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10 प्रतिशत) द्वारा से पदोन्नति (चयन द्वारा से)	नियम 2001 के नियम 4 (ए) के तहत बार (25 प्रतिशत) से सीधी भर्ती द्वारा
68	निल	08

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचित रिक्तियों पर नियुक्ति अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सिविल) सं. 9883/2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

ध्यान दे: झारखंड सुपीरियर जुडिसियल में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद के 28 अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की स्थिति में, न्यायालय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सेवा, जैसा कि पत्र

सं 9593/एप्पेट दिनांक 17 जुलाई 2012 को, इस कोटे [यानी नियम 4 (बी) के तहत] के तहत वास्तविक रिक्ति को घटाकर 40 कर दिया जाएगा।

आदेश के अनुसार

एसडी/-

महापंजीयक

तारीखः19 सितंबर, 2012"

9. यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2012 को रिक्तियों की स्थिति को संबंधित समय पर 174 की स्वीकृत संख्या के आधार पर अधिसूचित किया गया था। उस स्वीकृत संख्या को बाद में मौजूदा संख्या के 10 प्रतिशत की दर से वरिष्ठ अधिकारियों के 17 स्थायी पदों के निर्माण पर बढ़ाकर 191 कर दिया गया। उत्तर शपथ पत्र के पैराग्राफ 20 में, संशोधित नियमों (14 दिसंबर 2011 को संशोधित) के आधार पर गणना की गई रिक्ति की स्थिति का उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः

स्वीकृत शक्ति	योग्यता-सह-वरिष्ठता (65 प्रतिशत) के आधार पर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) से पदोन्नति द्वारा-नियम 4 (बी)	पदोन्नति (सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से चयन द्वारा से)-नियम 4 (सी)	बार से सीधी भर्ती (25 प्रतिशत)-नियम 4 (ए)
स्वीकृत शक्ति-191	124	19	48
वर्तमान कार्य शक्ति-124	68	20(-1*)	36

वर्तमान रिक्तियां	56-1*=55 (*अतिरिक्त समायोजित)	नील	12

10. तब यह कहा जाता है कि इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार-सिविल अपील सं.6647-6649/2012 (अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों, फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में तैनात अधिकारियों द्वारा दायर), 20 फरवरी 2013 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से उक्त सिविल अपीलों में 22 अपीलार्थियों को समायोजित करने के लिए 13 स्थायी पद बनाने का अनुरोध किया गया था, इस शर्त पर कि इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के संदर्भ में आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रिया में किसी भी अपीलार्थी के अयोग्य होने की स्थिति में, जिला न्यायाधीश के ऐसे सृजित पदों की समान संख्या को समाप्त कर दिया जाएगा। उचित विचार के बाद, झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस की रिक्ति की स्थिति को 22 फरवरी 2013 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था जो इस प्रकार हैः

"झारखंड का उच्च न्यायालय, रांची अधिसूचना

झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस की रिक्तियों की स्थिति, जैसा कि 19 सितंबर, 2012 की अधिसूचना सं. 275/ए द्वारा पहले अधिसूचित किया गया था, को याद किया जाता है और अब तक निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाता हैः-

नियम, 2001 के नियम 4 (बी) के तहत योग्यता-सह-वरिष्ठता (65 प्रतिशत) के आधार पर सिविल न्यायाधीश (सीनियर	नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10 प्रतिशत) द्वारा से पदोन्नति	बार (25 प्रतिशत) से सीधी भर्ती द्वारा-नियम, 2001 के नियम 4 (ए) के तहत

डिवीजन) से पदोन्नति द्वारा	(चयन द्वारा से)	
55	निल	22*+03%=25

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचित रिक्तियों पर नियुक्ति विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 9883/2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

ध्यान दें: 1. सिविल अपील सं.6647,6648 और 6649/2012 के अपीलार्थियों के लिए 22 रिक्तियां।

2. बार से सीधी भर्ती के लिए 03 रिक्तियां।

3. राज्य सरकार के अंत से 13 पदों के सृजन की संभावना है।

आदेश के अनुसार

एस. डी./- ए के चौधरी

महापंजीयक आई/सी

तारीखः22 फरवरी, 2013

ज्ञापन सं. 1644/Apptt रांची, तारीख 22 फरवरी, 2013

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की आधिकारिक वेबसाइट पर उपरोक्त अधिसूचना को तुरंत अपलोड करने के लिए इसकी प्रति आई/सी एन. आई. सी. प्रकोष्ठ, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची को भेजी जाती है।

एस. डी./- 22.02.2013

महापंजीयक आई/सी "

11. यह भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने 18 फरवरी 2014 के कार्यवृत्त के माध्यम से 20 फरवरी 2014 को रिक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन निम्नानुसार कियाः

एस. आई. नं.		स्वीकृत शक्ति	20.02.2014 पर कार्य करने की शक्ति	20.02.2014 पर वैकेंसी
1	नियम, 2001 के नियम 4 (बी) के तहत योग्यता-सह-वरिष्ठता (65 प्रतिशत) के आधार पर सिविल न्यायाधीश से पदोन्नति द्वारा	134	60	74" (74-4*)=70
2	नियम, 2001 के नियम 4 (सी) के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा (10 प्रतिशत)	21	17	4

	द्वारा से पदोन्नति (चयन द्वारा से)			
3	नियम, 2001 के नियम 4 (ए) के तहत बार (25 प्रतिशत) से सीधी भर्ती द्वारा	51	55	अतिरिक्त 4 * (अतिरिक्त समायोजित किया जा सकता है)

महापंजीयक द्वारा उच्च न्यायालय की ओर से दायर अन्य हलफनामों में उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को दोहराया गया है।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। प्रमुख अपील 2008 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने उक्त चयन प्रक्रिया को इस निष्कर्ष पर दरकिनार कर दिया है कि 50 प्रतिशत पद पहले ही योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों द्वारा भरे जा चुके हैं और जिसके परिणामस्वरूप 42 से अधिक रिक्तियों को सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीश/सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) से पदोन्नति और समान अनुपात में सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अनुपात बनाए रखने का प्रावधान करने वाले संशोधित नियम 20 अगस्त 2004 को प्रभावी हुए और इसके संभावित आवेदन थे। इस प्रकार, 20 अगस्त 2004 को प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति प्रासंगिक हो जाएगी।

13. नियम 4 और 5 को नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि यह 20.08.2004 के संशोधन से पहले मौजूद था।

नियम-4:- सेवा में नियुक्ति-सेवा में नियुक्ति, जो पहली बार में सामान्य रूप से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर होगी, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगीः-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड (2) के तहत ऐसी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) झारखंड सेवा से संबंधित अधिकारियों में से योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा बशर्ते कि जहां अधिकारियों की योग्यता सभी मामलों में समान हो, वरिष्ठता प्रबल होगी और उन्हें महत्व दिया जाएगा।

नियम-5:सेवा संवर्ग के कुल पदों में से 67 प्रतिशत पदोन्नतियों द्वारा और 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगेः

बशर्ते कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, समय-समय पर किसी भी दिशा में उपरोक्त प्रतिशत से विचलन कर सकती है।

नियम 8:-8. वरिष्ठताः

(क) सीधी भर्तियों की वरिष्ठता सेवा में उनकी संबंधित नियुक्तियों की तारीखों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ख) पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण इन नियमों के तहत उनकी नियुक्ति से तुरंत पहले झारखंड न्यायिक सेवा में उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

(ग) यदि किसी भी समय सेवा में एक से अधिक प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्ति

की जाती है, तो ऐसे नियुक्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी नियुक्ति के समय चयन सूची में प्राप्त योग्यता के आदेश के अनुसार किया जाएगा।

(घ) पदोन्नत अधिकारियों की तुलना में प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण उन तारीखों के संदर्भ में किया जाएगा जिन पर उनकी नियुक्तियां वास्तव में की जाती हैं।

बशर्ते, जब एक ही तिथि पर एक सीधी भर्ती और एक पदोन्नत अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो पदोन्नत अधिकारी सीधी भर्ती से वरिष्ठ रैंक का होगा।"

14. नतीजतन, 2004 से पहले की गई नियुक्तियां संबंधित समय पर लागू नियमों द्वारा शासित थीं। उस व्यवस्था के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्ती कोटा कुल पदों का 33 प्रतिशत था। यह स्पष्ट रूप से संशोधित नियमों में अब निर्दिष्ट 25 प्रतिशत से अधिक था (जैसा कि इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार 20.08.2004 पर संशोधित किया गया है)। विशेष रूप से, झारखंड राज्य ने सी ए सं 1867/2006 में एक शपथ पत्र दायर किया था। इस न्यायालय के समक्ष जिसमें यह कहा गया है कि उस समय झारखंड राज्य में सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ कोई रिक्ति मौजूद नहीं थी। संशोधित नियमों को अधिसूचित किए जाने और 20 अगस्त 2004 से लागू होने के बाद यह शपथ पत्र 26 अगस्त 2008 को दायर किया गया था। इस प्रकार, झारखंड के अधीनस्थ न्यायाधीशों के सदस्यों में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 34 पदों को भरने के लिए अधिसूचना 2008 में इस आधार पर जारी की गई थी कि सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले और योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर 18 पद इस आधार पर हैं कि प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के पदों के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा दायर शपथ पत्र में अब भी इस रुख को दोहराया गया

है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के खिलाफ एक निष्कर्ष दर्ज करने से पहले प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए रिक्त पदों के बारे में इन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं करने में स्पष्ट त्रुटि की है और उनके इस रुख को खारिज कर दिया है कि प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी।

15. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य में इस न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया है। अन्य भारत संघ और अन्य जिसने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद के लिए रोस्टर के सिद्धांत और पालन किए जाने वाले अनुपात को स्पष्ट किया है। निर्विवाद रूप से, इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमों में संशोधन किया गया था, जो 20 अगस्त 2004 से लागू हुआ था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ ए 27 से 29 में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पद पर भर्ती की विधि के बारे में प्रश्न पर विचार किया है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

"27. एक अन्य प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह है उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदों पर भर्ती की विधि। वर्तमान समय में, उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए दो स्रोत हैं, अर्थात् अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की इमारत की नींव है, इसलिए, किसी भी अन्य नींव की तरह, यह अनिवार्य है कि इसे होना चाहिए। जितना हो सके उतना मजबूत बनें। न्यायिक प्रणाली पर भार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर निर्भर करता है, हालांकि हमने शेट्टी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान में वृद्धि होगी, साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी, जो मेहनती हैं, अधिक कुशल बनें। यह आवश्यक है कि वे कानून के ज्ञान और नवीनतम घोषणाओं से अवगत रहें, और यही

कारण है कि शेट्टी आयोग ने एक न्यायिक अकादमी की स्थापना की सिफारिश की है, जो बहुत आवश्यक है। साथ ही, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के लिए कुछ निश्चित न्यूनतम मानक, वस्तुनिष्ठ रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक सेवा, यद्यपि हम शेट्टी आयोग से सहमत हैं कि अधिवक्ताओं में से उच्च न्यायिक सेवा अर्थात जिला न्यायाधीश संवर्ग में भर्ती 25 प्रतिशत होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होनी चाहिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए। इसके अलावा, अपेक्षाकृत कनिष्ठ और अन्य अधिकारियों के बीच सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी प्रोत्साहन होना चाहिए ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और तेजी से पदोन्नति प्राप्त कर सकें। इस तरह, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता में और सुधार होगा। इसे प्राप्त आदेशने के लिए, जबकि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत और सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत नियुक्ति का 50 अनुपात बनाए रखा जाता है, तथापि, हमारी राय है कि जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है, दो तरीके होने चाहिएः उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों का प्रतिशत योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए, इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालयों को उन उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान का पता लगाने और जांच आदेशने और मामले-कानून के पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरंतर दक्षता का आकलन आदेशने के लिए एक परीक्षा तैयार आदेशनी चाहिए और विकसित आदेशनी चाहिए। सेवा में शेष 25 प्रतिशत पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा

भरा जाएगा, जिसके लिए सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में योग्यता सेवा पांच साल से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इस संबंध में एक नियम बनाना होगा।

28. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में भर्ती होगीः

(1) (क) योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत;

(ख) कम से कम पाँच वर्ष की योग्यता रखने वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत सेवा; और

(ग) 25 प्रतिशत पदों को संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(2) उच्च न्यायालयों द्वारा यथासंभव शीघ्र उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे।

29. अनुभव से पता चला है कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों में सेवा में उनकी वरिष्ठता के संबंध में लगातार असंतोष रहा है। तीन दशकों से अधिक समय से दो अलग-अलग स्रोतों, अर्थात् पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती से भर्ती किए गए अधिकारियों से सापेक्ष वरिष्ठता तय आदेशने के लिए बड़ी संख्या में मामले शुरू किए गए हैं। आज के निर्णय के परिणामस्वरूप, एक तरह से उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के तीन तरीके होंगे। पदोन्नति के लिए जो कोटा हमने निर्धारित किया है, वह योग्यता-सह-श्रेष्ठता के सिद्धांत का पालन करते हुए 50 प्रतिशत, सीमित विभागीय प्रतियोगी

परीक्षा द्वारा योग्यता पर सख्ती से 25 प्रतिशत और सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत है। अनुभव से यह भी पता चला है कि जहां तक वरिष्ठता का संबंध है, देश में सबसे कम मुकदमेबाजी, जहां भर्ती में आरक्षण प्रणाली मौजूद है, वहां रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के टी. सी. नियमों के अनुसार, एक 40-सूत्री सूची निर्धारित की गई है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। शायद ही कभी, कोटा के अनुसार उनकी भर्ती के बाद सेवा के सदस्यों के बीच कोई मुकदमा हुआ हो, वरिष्ठता रोस्टर अंकों द्वारा तय की जाती है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि किसी व्यक्ति की भर्ती कब की जाती है। जब रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है, तो किसी भी विवाद के उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य 3 वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा 40-सूत्री सूची पर विचार किया गया है और उसे मंजूरी दी गई है, किसी भी मुकदमे से बचने और इस संबंध में निश्चितता लाने का एक तरीका पदों के संबंध में कोटा निर्दिष्ट करना है न कि रिक्तियों के संबंध में। यह मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर 40-बिंदु रोस्टर काम करता है। हम उच्च न्यायालयों को आर. के. सभरवाल मामले 3 में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित रोस्टर सिद्धांत के आधार पर उपयुक्त रूप से संशोधन करने और वरिष्ठता नियमों को जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश देते हैं। हम आशा करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता के निर्धारण में आगे कोई विवाद नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली केवल संभावित रूप से लागू हो सकती है, सिवाय इसके कि प्रासंगिक नियमों के तहत वरिष्ठता कोटा और आवर्तन प्रणाली के आधार पर निर्धारित की जानी है। उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मौजूदा सापेक्ष वरिष्ठता की रक्षा की जानी चाहिए लेकिन भविष्य के लिए रोस्टर विकसित किया जाना चाहिए। उपयुक्त नियमों और विधियों को उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया जाएगा और राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जहां भी 31-3-2003 द्वारा

आवश्यक होगा।"

(जोर दिया गया)

16. एक बार जब यह पाया जाता है कि 30 अप्रैल, 2008 तक सीधी भर्ती के कोटे के खिलाफ कोई पद उपलब्ध नहीं था, तो झारखंड उच्च न्यायिक द्वारावा के संवर्ग में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में रिक्तियों को भरने के प्रभाव को 25:25 के अनुपात में कम कर दिया है जो अनिवार्य रूप से 30.04.2008 पर प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पदों के कोटे से अधिक होगा। यह रोस्टर बिंदु को बाधित करेगा और संशोधित नियम 8 के संदर्भ में अस्वीकार्य है। नियम 5 और 8 में संशोधन करने वाली अधिसूचना दिनांक 20.08.2004 इस प्रकार हैः

"झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग और

राजभाषा

अधिसूचना

रांची तिथि 20.08.2004

नं. 6/एस्टाब्लिश्ड जूड 610/2001 पेर्सो. 4544/झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज (भर्ती, नियुक्ति और सेवाओं की शर्तें) के मौजूदा नियम 53 7 8 (डी) को निरस्त करने के बाद विभागीय अधिसूचना संख्या 1246 दिनांक 08.05.2001, नियम 5 और 8 (डी) के नियम 2001 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः- *

नियम 5: सेवा संवर्ग के कुल पदों में से।

(i) 50 प्रतिशत को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उप-न्यायाधीशों में से

पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण की जाएगी।

(ii) कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले उप-न्यायाधीशों की सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से योग्यता के आधार पर और अतीत में उनके सेवा रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखते हुए 25 प्रतिशत को पदोन्नति (चयन द्वारा से) द्वारा भरा जाएगा।

(iii) 25 प्रतिशत को उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर बार से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

8(घ) सीधी भर्तियों और पदोन्नति की वरिष्ठता तय करने के लिए नियुक्ति/पदोन्नति के बाद निम्नलिखित रोस्टर बनाए रखा जाएगा। अधिकारी। 100 पदों की प्रत्येक इकाई के लिए सूची इस प्रकार होगी।

(i) सेवा से अधिकारियों की पदोन्नति के लिए -

1,2, 5, 6,9, 10, 13, 14, 17, 18, 21,22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38,41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 97, 98.

(ii) उप-न्यायाधीश की सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा में अधिकारियों की पदोन्नति के लिए,

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99.

(iii) प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए -

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 88, 92, 96, 100.

राज्यपाल के आदेश से

(श्री नित्य शंकर मुखोपाध्याय)

राज्य के उप सचिव

नं. 6/एस्टाब्लिश्ड जूड 610/2001 पेर्सो. 4544/रांची तिथि 20.08.2004 के बाद

झारखंड के आधिकारिक राजपत्र के अगले संस्करण में प्रकाशित होने के अनुरोध के साथ अधीक्षक, सरकारी प्रेस, डोरंडा रांची को प्रतिलिपि बनाएँ।

सरकार के उप सचिव ",

17. 30 अप्रैल, 2008 को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2016 को दायर शपथ पत्र के पैराग्राफ 4 में कहा गया है, जो इस प्रकार हैः

“यह कहा गया है कि 30.04.2008 पर, झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस की स्वीकृत संख्या 145 थी और काम करने की संख्या 93 थी, जिसे नीचे दिखाया गया हैः-

उप-न्यायाधीशों से योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति (50 प्रतिशत)	सीमित प्रतियोगी परीक्षा (25 प्रतिशत) द्वारा से पदोन्नति (चयन द्वारा से)	बार से सीधी भर्ती द्वारा (25 प्रतिशत)
	स्वीकृत शक्ति-145	
73	36	36
	कार्य शक्ति = 93	
55	00	38
	रिक्तियां = 52	

18	36-2=34	02 (अधिशेष)

18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 30 अगस्त 2008 तक प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे में कोई रिक्ति मौजूद नहीं थी, रिट याचिकाकर्ताओं (प्रमुख अपील में 4 से 11 उत्तरदाता), जो सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति द्वारा से नहीं, केवल प्रत्यक्ष भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते थे, के पास 2008 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।

19. उच्च न्यायालय ने "पद" और "रिक्ति" के बीच के अंतर की अनदेखी की है। यदि प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा आवश्यक पद पहले ही समाप्त हो चुके थे, केवल इसलिए कि कुछ रिक्तियां होती हैं, तो इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति द्वारा सेवा में न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ यह खुला नहीं होगा। कैडर की ताकत को हमेशा कैडर वाले पदों की संख्या से मापा जाता है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा केवल दिए गए संवर्ग में एक पद के संबंध में किया जा सकता है। आरक्षण का प्रतिशत उन पदों की संख्या के संबंध में निर्धारित किया जाना चाहिए जो संवर्ग बनाते हैं और रिक्तियों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि चूंकि 30 अप्रैल, 2008 तक सीधी भर्तियों के लिए कोई पद मौजूद नहीं था, इसलिए सीधी भर्ती द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों के कहने पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से पदोन्नति द्वारा रिक्ति को भरने की चयन प्रक्रिया के लिए चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिए, ऐसे इच्छुक उम्मीदवारों (डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 4159/2008) द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

20. यह कहने के बाद, यह पालन करना चाहिए कि 2008 की चयन प्रक्रिया जो इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता के अनुसार पूरी की गई है, उचित है और अंतिम हो गई है। इस निष्कर्ष पर, वर्ष 2010 के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया के लिए सहयोगी रिट याचिकाओं में चुनौती हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। उसमें, 2010 में चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना की तारीख (यानी 4 नवंबर, 2010) की रिक्ति स्थिति, बार से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केवल 8 रिक्तियों तक थी। इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं में से कोई भी पहली 8 योग्यता सूची उम्मीदवारों के भीतर होने का दावा नहीं करता है। याचिकाकर्ताओं को क्रम संख्या 9 पर रखा गया था। पहले 8 उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद, 2010 के लिए चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और पूर्ण मानी जाएगी, केवल इसलिए कि रिट याचिकाकर्ताओं के नाम चयन सूची में दिखाई देते हैं, वे नियुक्त होने में कोई अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। रिक्तियों को मौजूदा विनियमों के अनुरूप भरा जाना है। चयन प्रक्रिया जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं ने भाग लिया, 8 अधिसूचित रिक्तियों के लिए उल्लिखित अधिसूचना के आधार पर शुरू की गई थी और मेधावी उम्मीदवारों की नियुक्तियां की गई हैं। उस चयन प्रक्रिया को समाप्त माना जाना चाहिए। तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा सीधी भर्ती के लिए विभिन्न या अधिक संख्या में पदों को अधिसूचित करते हुए जारी की गई बाद की चयन प्रक्रिया (2010 के बाद शुरू) के लिए अधिसूचनाएं 2010 की चयन प्रक्रिया के लिए कोई लाभप्रद नहीं हो सकती हैं। वह बदली हुई स्थिति सीधी भर्तियों के लिए पदों की उपलब्धता के आधार पर बाद की अवधि के लिए जिम्मेदार है 2010 की चयन प्रक्रिया के लिए नहीं। इसी तरह, यह तथ्य कि नियुक्त आठ उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने बाद में उचित चयन के बाद इस्तीफा दे दिया, 2010 की नियम 21 पर रखी गई निर्भरता चयन प्रक्रिया के पूरा होने पर रिट याचिकाकर्ता (गण) (ओं) को कोई अधिकार नहीं मिल सकता है जिसमें

चयन सूची तैयार करने और उसे अधिसूचित करने या अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध रहने की आवश्यकता होती है, भी अनुचित है। यह चयनित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए अनिवार्य नियम नहीं है। चयन सूची को बनाए रखने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है क्योंकि एक वर्ष की प्रतीक्षा सूची हमारे संज्ञान में लाई गई है। दूसरी ओर, नियम 22 का प्रभाव यह है कि एक बार जब अधिसूचित चयन सूची से उम्मीदवारों के नामों की नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में सरकार को सिफारिश की जाती है और अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है या चयन सूची को अधिसूचित करने से एक वर्ष की समाप्ति पर, विषय चयन प्रक्रिया के लिए चयन सूची अप्रभावी हो जाएगी। के लिए, उस चयन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए, कोई भी रिट याचिकाकर्ता उनके द्वारा दावा की गई राहत प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है।

21. राखी रे और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य के मामले में निर्णय. रिट याचिकाकर्ताओं के लिए कोई लाभ नहीं होगा और इसके बजाय हम पहले से ही लिए गए विचार का समर्थन करेंगे। रिट याचिकाकर्ताओं को 22 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार शुरू की गई चयन प्रक्रिया के आधार पर राहत का दावा करने के लिए नहीं सुना जा सकता है। उच्च न्यायालय से 2010 की चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापित रिक्तियों के अलावा रिक्तियों को भरने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा; चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने 2010 की पूर्व चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और वर्ष 2012 के लिए 22 फरवरी 2013 की अधिसूचना के आधार पर आयोजित बाद की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, इसलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सिविल अपील को सफल होना चाहिए और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। 29 अगस्त 2008 को डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 4159/2008 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को

दरकिनार कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 4159/2008 खारिज हो जाता है। यहां तक कि सं.300/2013,27/2014 और 325/2014 वाली तीन जुड़ी हुई रिट याचिकाएं भी खारिज किए जाने के योग्य हैं और खारिज कर दी जाती हैं। साथ में, आई. ए. को समान शर्तों में निपटाया जाता है।

23, हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

मामलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।